भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2535

उत्तर देने की तारीख 09/03/2026

देश में अनुसंधान एवं विकास में सुगमता

2535. **श्री लालजी वर्मा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 2025 में आईआईटी जम्मू में आयोजित अनुसंधान एवं विकास में सुगमता पर तीसरी क्षेत्रीय परामर्श बैठक के प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार उक्त सिफारिशों के आधार पर देश में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग में अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के लिए कोई नई नीति या योजना पर विचार कर रही है;

(ग) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा अनुसंधान के लिए वित्तपोषण प्रक्रिया को सरल बनाने और नौकरशाही संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): नीति आयोग द्वारा 14-15 जुलाई 2025 को आईआईटी जम्मू में "ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आर एंड डी)" पर तीसरी क्षेत्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। परामर्श बैठकों में भारत के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी को अनुपालन-संचालित ढांचे से सुविधा-उन्मुख, विश्वास-आधारित और परिणाम-केंद्रित प्रणाली में बदलने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। चर्चा किए गए प्रमुख सुधारों में वित्तपोषण और खरीद प्रक्रियाओं में सक्रियता बढ़ाना, संस्थागत अनुसंधान प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना, अधिक प्रतिभा गतिशीलता और प्रतिधारण को सक्षम

करना, प्रौद्योगिकी रूपांतरण तंत्र में सुधार करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप मजबूत निगरानी ढांचे को स्थापित करना शामिल है।

शैक्षणिक, उद्योग और उद्यम निर्माण के अनुसंधान एवं विकास संचालित एकीकरण के उद्देश्य से, इन संस्थानों के आसपास अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए आठ आईआईटी और आईआईएससी बेंगलुरु सहित प्रमुख उच्चरतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान पार्क स्थापित किए गए हैं। ये अनुसंधान पार्क उद्योग से वित्त पोषित अनुसंधान में सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे उद्योग-शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2018-19 में कुल 1650 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) योजना शुरू की। यह योजना भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली मेधा को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें छात्रवृत्ति और शोध अनुदान सहित बढ़ी हुई वित्तीय सहायता शामिल है। पीएमआरएफ के तहत 3688 शोधार्थियों को प्रवेश दिया गया है। पीएमआरएफ के पहले चरण से अनुसंधान के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और इस प्रकार, उन्नत वित्तीय सहायता के साथ तकनीकी अनुसंधान के लिए बजट वर्ष 2025-26 में पीएमआरएफ के तहत 10,000 छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) की स्थापना एएनआरएफ अधिनियम 2023 द्वारा फरवरी, 2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें निजी क्षेत्र से बजट योगदान का पर्याप्त हिस्सा प्रदान किया गया है।

सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को 1 लाख करोड़ रुपए की पहल, अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना भी शुरू की है, जो भारत के अनुसंधान और विकास परिदृश्य को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार ने अनुसंधान प्रयोजन के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोज्य वस्तुओं की खरीद की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है और वैज्ञानिक मंत्रालय/विभागों/संगठनों के तहत शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों/कुलपति को अनुसंधान गतिविधियों के हित में ऐसी खरीद के लिए औचित्य के अध्यधीन, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 161(IV) के तहत 200 करोड़ रुपये तक की वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) जारी करने की मंजूरी देने की शक्तियां सौंपी हैं। संस्थागत स्वायत्तता

बढ़ाने और अनुसंधान खरीद में तेजी लाने के उद्देश्य से, सरकार ने वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोज्य वस्तुओं की खरीद के लिए जीएफआर, 2017 के नियम 154, 155, 161 और 162 के तहत मौद्रिक सीमा को भी संशोधित किया और बढ़ाया है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य, दीर्घकालिक शहरों, कृषि और शिक्षा के चार क्षेत्रों में अंतरविषयक अनुसंधान करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने और स्तरोन्नयन योग्य समाधान के लिए, सरकार ने चार आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेन्स (एआई) उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना भी की है, जिनमें से स्वास्थ्य, दीर्घकालिक शहर, कृषि और शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र में आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी मद्रास में क्रमशः स्थापित किया गया है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 1490.00 करोड़ रुपये है।

*****